विकासशील देशों पर संघर्षों का असर

संतुलित वैश्विक उपायों की जरूरत, बहुपक्षीय सहयोग और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर जोर : मंत्री सीतारमण

नई दिल्ली, 12 जून केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वैश्विक भू-राजनीतिक संघर्षों का सबसे अधिक प्रभाव विकासशील देशों और दक्षिणी गोलार्ध की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है. उन्होंने ऐसे देशों को इन संकटों से बचाने के लिए समन्वित वैश्विक कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया.

मंत्री सीतारमण ने भारत की आर्थिक प्रगति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' मंत्र से जोड़ते हुए बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था घरेलू मांग से संचालित है, और विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित होती है. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और अगले कुछ वर्षों में लगभग सात प्रतिशत की वृद्धि दर बनाए रखने की संभावना है.

श्रीमती सीतारमण 'ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ समिट' की वर्चुअल बैठक को नई दिल्ली से संबोधित कर रही थीं. यह बैठक जी7 देशों के समक्ष फ्रांस की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें भारत, ब्राजील, चीन, दक्षिण कोरिया, केन्या और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि भी शामिल हुए. इस अवसर पर विकासशील देशों ने अपनी दृष्टि प्रस्तुत की और संतुलित वैश्विक विकास की दिशा में सुझाव दिए.

वित्त मंत्री ने कहा कि हाल के वैश्विक घटनाक्रमों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लचीली, विविधीकृत और भौगोलिक रूप से वितरित आपूर्ति श्रृंखलाओं का महत्व अब पहले से कहीं अधिक है. उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा कि देश की वृद्धि मुख्यत: घरेलू मांग से संचालित है और वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है.

सीतारमण ने विशेष रूप से दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील और गरीब देशों पर वैश्विक अनिश्चितताओं के असंतुलित प्रभावों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, 'आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितताओं के दुष्परिणाम विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ पर असमान रूप से अधिक पड़ते हैं. इसे संतुलित करने के लिए समन्वित वैश्विक कार्रवाई जरूरी है.'

हाइब्रिड कारों पर टैक्स राहत पर फैसला अटका

नई दिल्ली, 12 जून दिल्ली सरकार की नई ईवी नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक प्रोत्साहन देने की तैयारी है, लेकिन हाइब्रिड वाहनों को मिलने वाली संभावित टैक्स राहत ने नीति निर्माताओं के बीच बहस छेड़ दी है. एक पक्ष पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का समर्थक है, जबकि दूसरा पक्ष हाइब्रिड वाहनों को ईवी की ओर संक्रमण का व्यावहारिक विकल्प मान रहा है.

करीब 3,954 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट वाली इस महत्वाकांक्षी नीति का उद्देश्य राजधानी में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है. हालांकि, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों को रोड टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट देने के प्रस्ताव ने इसके अंतिम स्वरूप को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है.

स्विट्जरलैंड दौरे पर पहुंचे मंत्री पीयूष गोयल

दो दिवसीय उच्चस्तरीय दौरा आज से शुरू

यूरोपीय बाजारों में भारत की पहुंच बढ़ाने पर जोर

नई दिल्ली, 12 जून केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से स्विट्ज़रलैंड की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं. इस दौरान वह भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित उच्चस्तरीय वार्ताएं करेंगे.

मंत्रालय के अनुसार यह यात्रा भारत की यूरोपीय साझेदारों के साथ आर्थिक संबंधों को विस्तार देने की रणनीति का हिस्सा है. ईएफटीए समूह में स्विट्ज़रलैंड के साथ-साथ नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन शामिल हैं. भारत ने मार्च 2024 में इस समूह के साथ व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ.

दौरे के दौरान गोयल स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न में वहां की सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे. इन बैठकों में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने, निवेश प्रवाह को गति देने और औद्योगिक सहयोग को विस्तारित करने पर चर्चा की जाएगी.

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री की मुलाकात स्विट्ज़रलैंड की आर्थिक मामलों की मंत्री हेलेन बुडलिगर आर्टिएडा तथा स्विट्ज़रलैंड के संघीय राष्ट्रपति गाइ पार्मेलिन से भी होगी.

> सरकारी सूत्रों के अनुसार यह दौरा भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत यूरोप के विकसित देशों के साथ आर्थिक संबंधों को नए स्तर पर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है. ईएफटीए के साथ समझौता भारत के लिए यूरोपीय बाजारों में निर्यात बढ़ाने और विदेशी निवेश आकर्षित करने का महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है. समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन से भारतीय उद्योगों, विशेषकर विनिर्माण, फार्मा और सेवा क्षेत्र को बड़ा लाभ मिल सकता है. इससे न केवल निर्यात बढ़ेगा बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी भी मजबूत होगी.

शेयर बाजारों में जबरदस्त तेजी

सेंसेक्स 1,695 अंक उछला

मुंबई, 12 जून अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीद में शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजारों में जबरदस्त तेजी देखी गयी. बीएसई का सेंसेक्स 1,695 अंक ऊपर बंद हुआ.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद कि ईरान के साथ शांति वार्ता में काफी प्रगति हुई है और इस सप्ताहांत पर समझौता संभव है, दुनिया भर में शेयर बाजारों में तेजी रही और कच्चा तेल गिर गया. हालांकि ईरान ने ऐसी किसी ठोस प्रगति से इनकार किया है. ट्रंप के बयान से उत्साहित निवेशकों की लिवाली से सेंसेक्स 876 अंक चढ़कर खुला. दोपहर बाद बाजार में लिवाली और बढ़ी. अंत में यह 1,695.40 अंक (2.30 प्रतिशत) की बढ़त में 75,527.95 अंक पर बंद हुआ. यह 29 मई के बाद का इसका उच्चतम स्तर है.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 461.30 अंक यानी 1.99 प्रतिशत की तेजी के साथ 23,622.90 अंक पर बंद हुआ जो 27 मई के बाद का इसका सबसे ऊंचा बंद स्तर है. चौतरफा लिवाली के बीच वृहत बाजार में भी तेजी रही.

निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 2.37 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 2.80 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ. आईटी को छोड़कर अन्य सभी सेक्टरों के सूचकांक ऊपर रहे. बैंकिंग, वित्त, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद, रियल्टी, ऑटो और तेल एवं गैस सेक्टरों में निवेशकों ने खूब पैसा लगाया.

> सेंसेक्स की कंपनियों में बजाज फाइनेंस का शेयर साढ़े पांच फीसदी से अधिक चढ़ा. एलएंडटी तथा इंडिगो में साढ़े चार से पांच प्रतिशत तक और टाइटन, इटरनल तथा एचडीएफसी बैंक में साढ़े तीन से चार प्रतिशत तेजी रही. बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक और मारुति सुजुकी के शेयर दो से तीन प्रतिशत के बीच चढ़े. टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेंट, भारतीय स्टेट बैंक, अडानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीसीएस, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनीलिवर और बीईएल के शेयर एक से दो प्रतिशत की बढ़त में रहे. एनटीपीसी और सन फार्मा में भी तेजी रही.

ट्रेन में लोअर बर्थ पाने के पाए मौके

नई दिल्ली, 12 जून. भारतीय रेलवे में यात्रा के दौरान लोअर बर्थ सबसे ज्यादा मांग वाली सीटों में शामिल है. बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह अधिक सुविधाजनक मानी जाती है.

हालांकि आईआरसीटीसी पर लोअर बर्थ प्रेफरेंस चुन लेने मात्र से इसकी गारंटी नहीं मिलती. कुछ सावधानियां और सही समय पर की गई बुकिंग लोअर बर्थ मिलने की संभावना बढ़ा सकती है.

रेलवे यात्रियों को टिकट बुकिंग के दौरान बर्थ प्रेफरेंस चुनने का विकल्प देता है. यात्री लोअर बर्थ का चयन कर सकते हैं, लेकिन अंतिम सीट आवंटन उपलब्धता और आरक्षण प्रणाली के आधार पर किया जाता है. इसलिए कई बार लोअर बर्थ चुनने के बावजूद यात्रियों को मिडिल या अपर बर्थ आवंटित हो जाती है.झ

रेलवे के नियमों के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को लोअर बर्थ आवंटन में प्राथमिकता दी जाती है. सामान्यत: 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष तथा 58 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को उपलब्धता के आधार पर लोअर बर्थ कोटा का लाभ मिल सकता है.

सोना-चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल

1500 रुपए उछला सोना

9,700 रुपए महंगी हुई चांदी

नई दिल्ली, 12 जून 2026. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय सर्राफा बाजार में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में जोरदार तेजी दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूती और निवेशकों की बढ़ती मांग के चलते दोनों कीमती धातुओं के दाम फिर ऊपर चढ़ गए हैं.

12 जून को सोना एक बार फिर रुपए 1.47 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गया, जबकि चांदी में भी तेज उछाल देखने को मिला और यह 2.42 लाख प्रति किलो से ऊपर पहुंच गई. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के ताजा रेट्स के मुताबिक, 24 कैरेट सोना 147,609 प्रति 10 ग्राम, 23 कैरेट सोना 147,018 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 135,210 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया. वहीं चांदी की कीमत 242,000 से 243,000 प्रति किलो के आसपास कारोबार करती दिखी. सोने के दामों में आज करीब 1,500 प्रति 10 ग्राम तक की तेजी देखने को मिली है (पिछले सत्र की तुलना में). 24 कैरेट सोना 10 ग्राम में फिर से मजबूत होकर 1.47 लाख के पार चला गया, जिससे निवेशकों को हाल की गिरावट के बाद राहत मिली है. चांदी ने आज सोने से भी तेज रफ्तार दिखाई. 10 ग्राम के हिसाब से देखें तो चांदी में लगभग 90 से 100 प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई है.

संकट रोकने को सेबी को मिलेगी अधिक ताकत

नई दिल्ली, 12 जून भारत के तेजी से विस्तार कर रहे पूंजी बाजार में संभावित संकटों को समय रहते रोकने के लिए संसदीय वित्त संबंधी स्थायी समिति ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को अधिक शक्तियां देने का समर्थन किया है. समिति का मानना है कि निवेशकों के हितों की बेहतर सुरक्षा और बाजार की स्थिरता के लिए नियामक ढांचे को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है. भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष भर्तृहरि महताब ने कहा कि भारत एक तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है, जहां पूंजी बाजार का विस्तार अभूतपूर्व गति से हो रहा है. ऐसे में किसी भी संभावित वित्तीय संकट को पहले ही रोकने के लिए सेबी को पर्याप्त अधिकार और संसाधन उपलब्ध कराना जरूरी है.

भारतीय कपड़ा उद्योग में लौटा उत्साह

उद्योग की बुनियादी दक्षता और लाभप्रदता बढ़ी

वैश्विक खरीदार भारत को पसंद कर रहे

नई दिल्ली, 12 जून. डोलाट कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी शुल्कों में कमी और वैश्विक मांग में सुधार से भारतीय कपड़ा उद्योग ने सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए हैं. उद्योग के बुनियादी सिद्धांत मजबूत हुए हैं और मुक्त व्यापार समझौतों ने भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूती दी है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि फरवरी 2026 के अंत में अमेरिकी कपड़ा उत्पादों पर 50% तक लगे शुल्क घटाकर केवल 10% कर दिए गए. इससे भारतीय निर्यातकों को राहत मिली और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बहाल हुई. अमेरिकी बाजार में रुकी हुई मांग भी अब खुलकर सामने आ रही है, जिससे निर्यात में तेजी आई है.

उद्योग के बुनियादी ढांचे में भी सुधार हुआ है. कताई खंड में क्षमता का समेकन हुआ, जिससे उत्पादन दक्षता बढ़ी है. कपास की लागत प्रतिस्पर्धा बहाल होने और यार्न के प्रसार में सुधार से पूरे मूल्य श्रृंखला में लाभप्रदता बेहतर हुई है.

पर्सनल लोन से पहले रखें दस्तावेज तैयार

नई दिल्ली, 12 जून. पर्सनल लोन की बढ़ती लोकप्रियता के बीच बैंकों ने ऋण प्रक्रिया को पहले से अधिक आसान बना दिया है. अब लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर कुछ ही घंटों में लोन राशि प्राप्त कर सकते हैं.

हालांकि, लोन मंजूरी की प्रक्रिया को तेज और सरल बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखना बेहद महत्वपूर्ण है. निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन आज सबसे पसंदीदा वित्तीय विकल्पों में से एक बन गया है.

कच्चे तेल में नरमी से रुपया मजबूत

मुंबई, 12 जून कच्चे तेल में नरमी और विदेशों में बॉन्ड यील्ड घटने से शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में रुपये में अच्छी मजबूती देखी गयी. अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में भारतीय मुद्रा 45 पैसे की बढ़त के साथ 95.40 रुपये प्रति डॉलर पर खुली. खबर लिखे जाते समय यह 57 पैसे की मजबूती में 95.28 रुपये प्रति डॉलर पर थी.

पिछले कारोबारी दिवस पर 60 पैसे गिरकर रुपया 95.85 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था.अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीद से कच्चे तेल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट है, शेयर बाजार बढ़त में हैं और बॉन्ड यील्ड घट गया है.अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि ईरान के साथ शांति वार्ता काफी आगे पहुंच गयी है. इसमें इतनी प्रगति पहले कभी नहीं हुई थी और इस सप्ताहांत पर समझौता संभव है. इसके बाद कच्चे तेल का मानक लंदन का ब्रेंट क्रूड वायदा एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ 90 डॉलर प्रति बैरल से नीचे उतर गया.

समाचार विशेष

मालवा : 69 सीटों की जंग रोचक

मिशन 2027 के लिए क्यों है अहम?

चंडीगढ़. पंजाब की सियासत में सबसे अहम क्षेत्र है मालवा, केवल इसलिए नहीं कि कुल 117 विधानसभा सीटों में से 69 इसी क्षेत्र में हैं बल्कि इसलिए भी कि इस इलाके से उठी सियासी लहर पूरे पंजाब में सियासत के रुख को बदल देती है.

राजनीति हो या किसानी आंदोलन यहां के नेता और बाशिंदों ने बखूबी अपना दम दिखाया है. कद्दावर नेताओं के साथ-साथ बड़ी किसान जत्थेबंदियां का मालवा से संबंध है. पंजाब के सभी राजनीतिक दल इस क्षेत्र का सियासी महत्व जानते हैं लिहाजा साल 2027 के मद्देनजर नेताओं ने इस क्षेत्र पर अपना फोकस और सक्रियता बढ़ा दी है. इसके इतर मालवा के मतदाताओं की खास बात यह है कि यहां के लोगों ने सभी दलों को परखा, समझा और फिर अपनी सेवा का मौका दिया. पिछले पांच विधानसभा चुनावों का ट्रेंड इसी बात को साबित करता है. यही वजह है कि भाजपा को छोड़कर कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और आम आदमी पार्टी इस क्षेत्र को अपना-अपना गढ़ मानते रहे हैं मगर यहां मतदाताओं का मिजाज पढ़ना आसान नहीं है.

साल 2002 के विधानसभा चुनाव का परिणाम देखें तो कांग्रेस को यहां सबसे ज्यादा 29 सीटें मिली थीं जबकि 27 सीटों के साथ शिअद दूसरे नंबर पर थी. साल 2007 में मालवा की 37 सीटें कांग्रेस जीती थी जबकि अकालियों के खाते में 19 सीटें आई थीं. साल 2012 में शिअद ने 34 सीटों पर कब्जा किया जबकि कांग्रेस 31 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई. साल 2017 में कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर मालवा में दोबारा जलवा दिखाया जबकि अकाली 8 सीटों पर सिमट गए. इसी चुनाव में सूबे में नया दल आम आदमी पार्टी (आप) ने पहली बार इस इलाके से 18 सीटें जीती. साल 2022 के चुनाव में मालवा के मतदाताओं ने आप पर इतना प्यार लुटाया कि पार्टी ने इस क्षेत्र की 69 में से 66 सीटों पर कब्जा किया. कांग्रेस 2 और अकाली 1 सीट पर सीमित रह गए. मतदाताओं का यह रुझान बताता है कि यहां के बाशिंदे लहर के साथ चलते हैं.

अपना-अपना पार्टी सर्वे

इन दिनों मालवा की सियासी महत्ता फिर बढ़ी हुई है क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव सिर पर हैं. सभी दल इन इलाकों में अपना-अपना पार्टी सर्वे करवा रहे हैं. कांग्रेस करवा चुकी है. बठिंडा, मानसा, सरदूलगढ़, मोड़ मंडी, रामपुरफूला, तलवंडी साबो इत्यादि क्षेत्रों में किसान वर्ग निर्णायक बनता है. साल 2022 के परिणामों में यहां दबदबा तो आप का है मगर कांग्रेस और अकाली यहां दोबारा अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं जबकि भाजपा के लिए यहां खोने के लिए कुछ नहीं है. लिहाजा सभी दलों ने यहां ताकत झोंकनी शुरू कर दी है.

नीतीश के वोट बैंक में सम्राट की सेंधमारी

एमएलसी चुनाव के बहाने कर दी 35 प्रतिशत वोट की राजनीति

पटना. बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार के बरक्स बीजेपी के रणनीतिकार ने अपनी राजनीति को एक नया रुख देना शुरू कर दिया है. भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में यह कहा जाता है कि हमेशा चुनावी मूड में रहती है, उसकी एक खास विशेषता यह भी है कि खुद को किसी दल के बिना भी चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी भी करती रहती है.

राज्य में हुए 9 सीटों के द्विवार्षिक चुनाव और दो सीटों पर हुए उप चुनाव में बीजेपी ने बगैर शोरगुल किए नीतीश कुमार के अतिपिछड़े वोट बैंक पर डोरे डालना शुरू भी कर दिया है. देखिए बीजेपी के रणनीतिकार ने रूष्ट के चुनाव में कौन सा दांव खेल डाला है.

बीजेपी का अतिपिछड़ा कार्ड-राज्य में हुए 9 सीटों के द्विवार्षिक चुनाव और दो सीटों पर हुए उप चुनाव में बीजेपी की हिस्सेदारी में चार द्विवर्षीय और एक उप चुनाव वाली सीट मिली. तीन बीजेपी से सवर्ण को दी. मंगल पांडेय की खाली सीट से अरविंद शर्मा को दी. द्विवार्षिक चुनाव की चार सीटों में से दो सवर्ण संजय मयूख और पवन सिंह को सीट दी. दो अति पिछड़ा में नाई जाति से अनिल कुमार ठाकुर को और प्रजापति यानी कुम्हार जाति से शिवानी पंडित को मौका दिया. बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने अभी तक नाई जाति और कुम्हार जाति से किसी को भी रूष्ट नहीं बनाया.

गहलोत के बयान से फिर गरमाई सियासत

पायलट के साथ विवाद सुर्खियों में ; भाजपा ने भी घेरा

जयपुर. राजस्थान की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयान ने नई सियासी चर्चा को जन्म दे दिया है. एक ओर कांग्रेस के भीतर इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने भी गहलोत के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक खींचतान एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत को इस बात का आभास हो गया है कि सचिन पायलट को भविष्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. यही कारण है कि वे लगातार बयान दे रहे हैं. राठौड़ ने इसे गहलोत की राजनीतिक हताशा करार दिया. वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अशोक गहलोत उन्हें निशाना बनाकर अपनी राजनीतिक खीझ निकालने का प्रयास कर रहे हैं. शेखावत का कहना है कि गहलोत समझ चुके हैं कि पार्टी में उनका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा है. दरअसल हाल ही में अशोक गहलोत ने 25 सितंबर 2022 के राजनीतिक घटनाक्रम और कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर खुलकर अपनी बात रखी थी. उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर मिलता तो वे उसे स्वीकार करते. गहलोत ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ यह धारणा बनाई गई कि वे मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते थे, जबकि वास्तविक स्थिति अलग थी. गहलोत ने 25 सितंबर के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय पर्यवेक्षकों के अचानक पहुंचने और मीडिया में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाओं के कारण विधायकों में असमंजस की स्थिति बन गई थी.

विशेष | **टीवीके सरकार बचाने वाले एआईएडीएमके के 21 बागियों को पार्टी ने किया माफ**

माफीनामा मंजूर और दुश्मनी खत्म!

चेन्नई. तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने मंगलवार को घोषणा की कि पिछले महीने हुए विश्वास मत के दौरान टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करने वाले 21 एआईएडीएमके विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई रद्द कर दी गई है.

पार्टी नेतृत्व ने विधायकों के स्पष्टीकरण और माफी को स्वीकार कर लिया है. यह घटनाक्रम 13 मई को 234 सदस्यीय विधानसभा में हुए विश्वास मत के संदर्भ में सामने आया है, जिसमें टीवीके सरकार ने आसानी से जीत हासिल की थी. विश्वास प्रस्ताव 144 मतों के पक्ष में और 22 मतों के विपक्ष में पारित हुआ, जबकि पांच सदस्यों ने मतदान से परहेज किया. मुख्य विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान वॉकआउट किया.

महत्वपूर्ण बात यह है कि एआईएडीएमके के 25 विधायकों ने सरकार के समर्थन में मतदान किया, जिससे विपक्षी दल के भीतर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया. मतदान के बाद, एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने दलबदल विरोधी प्रावधानों के तहत इन 25 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए अध्यक्ष को एक याचिका दी. मंगलवार को सचिवालय में पत्रकारों से बात करते हुए अध्यक्ष प्रभाकर ने कहा कि उन्हें इस मामले में पलानीस्वामी से चार अलग-अलग पत्र प्राप्त हुए थे. उन्होंने आगे कहा कि पत्रों की जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया कि एआईएडीएमके नेतृत्व ने 21 विधायकों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरणों को स्वीकार कर लिया है और विश्वास मत के दौरान उनके आचरण के लिए उन्हें क्षमा कर दिया है. प्रभाकर ने कहा कि एडप्पाडी के. पलानीस्वामी द्वारा 13 मई, 2026 को भेजे गए पत्र में उल्लिखित अनुसार, मैं संबंधित सदस्यों की माफी स्वीकार कर रहा हूं और उनके खिलाफ सभी आगे की कार्रवाई रोक रहा हूं.

4 विधायकों पर होगी कार्रवाई

तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि एआईएडीएमके प्रमुख ने शेष चार विधायकों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया था, जिनके स्पष्टीकरण को पार्टी नेतृत्व ने स्वीकार नहीं किया. इसी अनुरोध के आधार पर एआईएडीएमके विधायकों एस. जयकुमार, मरगथम कुमारवेल, सत्यबामा और इसाक्की सुब्बैया के खिलाफ औपचारिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. प्रभाकर ने कहा कि उचित प्रक्रिया पूरी होने के बाद चारों विधायकों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की प्रकृति की घोषणा बाद में की जाएगी.